

प्रेषक,

एम०एच० खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक-

०५ दिसम्बर
अक्टूबर, 2013

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत राजभवन, नैनीताल के जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 717/IV(2)-श०वि०-12-27(जेएनएनयूआर एम)/10, दिनांक 18.05.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जे०एन०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्धार एवं पुर्ननिर्माण परियोजना हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल ₹295.56 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-59(1)/PF1/2013-757, दिनांक 25.09.2013 द्वारा राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्धार एवं पुर्ननिर्माण परियोजना हेतु द्वितीय किस्त के रूप में ₹141.87 लाख की धनराशि, सी०एस०एम०सी० की 125वीं बैठक के क्रम में अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्धार एवं पुर्ननिर्माण परियोजना हेतु ₹141.87 लाख केन्द्रांश एवं ₹35.47 लाख राज्यांश अर्थात् कुल ₹177.34 लाख (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि कुल ₹177.34 लाख (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इसे वह पी०एल०ए० खाते में रखेंगे।
- (ii) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या: 717/IV(2)-श०वि०-12-27 (जेएनएनयूआर एम)/10, दिनांक 18.05.2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (iv) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (v) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (vi) निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15-12-2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
- (vii) आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (viii) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
- (ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2014 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक "4217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे ₹140.10 लाख, अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद के नामे ₹31.92 लाख तथा अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे ₹5.32 लाख डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं०-413/XXVII(2)/2013, दिनांक 10 जून, 2013 में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जारी किया जा रहा है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28-03-2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-s1312130034, s.1312300035 एवं s.13123100036 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

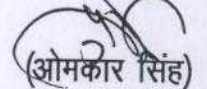
(एम०एच० खान)
प्रमुख सचिव।

सं० 1539 (1)/IV(2)-शा०वि०-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त अनुभाग-1/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
12. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नैनीताल।
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।